भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति और समस्याएं
Trends of Urbanization and its Problems in India

बोलेन्द्र कुमार अगम,
सहायक प्राध्यापक भूगोल,
राजा सिंह कॉलेज सिवान

नगरीकरण का अर्थ गांव से नगर की ओर जनसंख्या के गतिशील होने, ग्रामीण जीवन के नगरीय जीवन में परिवर्तित होने की प्रक्रिया तथा नगरीय केंद्रों के विकास तथा प्रसारण से है । इस प्रकार नगरीकरण ग्रामीण बस्तियों से नगरों में कार्य कायांतरित होने की एक समन्वित विधि है ।

भारत में नगरीकरण का इतिहास

भारत में प्राचीन काल से ही नगरीकरण के साक्ष्य मिलते है । इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी । हमारे देश में ऐसे अनेक नगर हैं, जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं । प्राचीन भारत में नगरों का अभ्युदय नदियों के किनारे, संगम पर तथा विस्तृत मैदानों में हुआ ।

मध्यकाल में सड़कों व सराय के निर्माण तथा व्यापार के विकास के कारण अनेक नगर स्थापित हुए ।

उपनिवेश काल में नगर विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया । रेल मार्ग और सडकों के विकास के फलस्वरुप अनेक नगर स्थापित हुए हैं ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में नगरीकरण की विस्फोटक प्रवृत्ति रही है जिसका मुख्य कारण ग्रामीण-नगरीय स्थानांतरण रहा है ।

भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति: 2011 की जनगणना के अनुसार 37,71,06,125 लोग शहरों में निवास करते हैं जो संपूर्ण जनसंख्या का 31.16% है । भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति को हम नीचे की सारणी के द्वारा समझ सकते हैं:

भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति

वर्ष	नगरीय जनसँख्या करोड़ में	कुल जनसँख्या में नगरीय जनसँख्या का प्रतिशत	दशक में नगरीय जनसँख्या में वृद्धिदर प्रतिशत में	नगरीय जनसँख्या में प्रतिशत वार्षिक का प्रतिशत वृद्धिदर
1901	2.59	10.84	.....	.....
1911	2.59	10.29	0.35	0.03
1921	2.81	11.18	8.27	0.79
1931	3.35	11.99	19.12	1.75
1941	4.42	13.86	31.97	2.77
1951	6.24	17.29	26.41	2.34
1961	7.89	17.97	26.41	2.34
1971	10.91	19.91	38.23	3.21
1981	15.95	23.34	46.14	3.83
1991	21.72	25.72	36.19	3.09
2001	28.61	27.81	31.72	3.13
2011	37.71	31.16	31.2	3.18

भारत में शहरीकरण के आंकड़े

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ मौजूदा वक़्त में दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी और तब तक विश्व की आबादी का सत्तर फीसद हिस्सा शहरों में रह रहा होगा।

- संयुक्त राष्ट्र के ही एक अन्य आंकड़े के मुताबिक साल 2018 से 2050 के बीच बढ़ने वाली आबादी में पैंतीस फीसद हिस्सेदारी भारत, चीन और नाइजीरिया की होगी। अनुमान है कि साल 2050 तक भारत में 41.6 करोड़, चीन में 25.5 करोड़ और नाइजीरिया में 18.9 करोड़ शहरी आबादी बढ़ जाएगी।
- ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के एक स्टडी के मुताबिक़ साल 2019 और 2035 के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाले सभी शीर्ष 10 शहर भारत में हैं।
- साल 2011 की जनगणना के मुताबिक़, हमारे देश की जनसंख्या का 31.16 फीसद हिस्सा शहरों में रहता है लेकिन अगर सेटेलाइट से मिली तस्वीरों को आधार बनाया जाए तो दो तिहाई यानी तिरसठ फीसद भारत शहरी नज़र आएगा।
- भारत की शहरी आबादी का लगभग 17.4% झुग्गी-झोपड़ी में रहता है।
- जनगणना 2011 के अनुसार 2.9% शहरी घर टूटे-फूटे हालत में हैं।
- शहरी ग्रीष्म द्वीप प्रभाव के कारण दिल्ली 4.12 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। आपको बता दें कि अर्बन हीट आइलैंड यानी शहरी ग्रीष्म द्वीप ऐसे महानगरीय क्षेत्र को कहा जाता है, जो मानवीय गतिविधियों के चलते अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों मुक़ाबले ज़्यादा गर्म होता है।
- शहरी क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 70% योगदान करते हैं लेकिन भूमि आधार पर मात्र 4% का हक़ रखते हैं।

नगरीय बस्ती

नगरीय बस्ती की मान्यता हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं:

- न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो
- पुरुष कार्यकारी जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो
- न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो
- वे सभी स्थान जहां नगरपालिका, नगरनिगम, सैनिक छावनी या अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यरत हो

वर्तमान में भारत सरकार के जनगणना विभाग द्वारा भारतीय नगरों को जनसंख्या आकार के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया है:

नगरीय वर्ग	जनसंख्या का आकार
वर्ग 1	1 लाख से अधिक
वर्ग 2	50,000 से 99,999
वर्ग 3	20,000 से 49,999
वर्ग 4	10,000 से 19,999
वर्ग 5	5,000 से 9,999
वर्ग 6	5,000 से कम

भारत में नगरीकरण की अवस्थाएं

- *मंद नगरीकरण 1901-31:* इस अवधि में अकाल, महामारी तथा उच्च मृत्यु दर के कारण नगरों की दशकीय वृद्धि सीमित रहे । नगरीय जनसंख्या में 0.98 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई ।

- *मध्यम नगरीकरण 1931-61:* इस अवधि में नगरीय जनसंख्या में 135.86% वृद्धि हुई । जबकि नगरीकरण का प्रतिशत 12.2 से बढ़कर 18.35 पहुंच गया । इसी दौरान नियोजित विकास प्रारंभ हुआ । उद्योग स्थापित हुए । विकास का आधार पुष्ट हुआ ।
- *तीव्र नगरीकरण 1961-2011:* 1961 के बाद नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि (50 वर्षों की अवधि में 377% से अधिक) हुई । वस्तुतः देश नगरीय विस्फोट की अवस्था से गुजर रहा है । नगरीय केंद्र आर्थिक क्रियाकलापों के केंद्र बन गए हैं जो ग्रामीण जनसंख्या को आकर्षित करते हैं ।

नगरीय बस्तियां

नगरीय बस्ती एक बड़ी सघन केंद्रीकृत वस्ती है जिसमें ज्यादातर श्रमबल द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में कार्य करती है । नगरीय स्थान को परिभाषित करने का कोई एक मापदंड नहीं है । इस मापदंड में एक देश से दूसरे देश तथा एक राज्य से दूसरे देश में भिन्नता देखी जा सकती है । सामान्यता नगरीय स्थानों की परिभाषा जनसंख्या के आकार, जनसंख्या घनत्व, निवासियों के व्यवसाय तथा स्थानीय सरकार के प्रकार पर आधारित है । परिभाषा के तौर पर,

'नगर क्षेत्रों का भौतिक विस्तार या उसके क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि में बेतहाशा वृद्धि नगरीकरण कहलाता है । यह एक वैश्विक परिवर्तन है ।'

संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार *'ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी नगरीकरण है ।'*

भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकार

नगरीय ग्राम (Urban Village): यह नगरीय विकास के संक्रमण अवस्था का द्योतक है जिसमें ग्रामीण और नगरीय कार्य मिश्रित रूप से देखे जा सकते हैं जैसे Rurban Centre, Market Town, Semi Urban Town, Rural Town आदि ।

कस्बा (Town): यह नगरीय अधिवास की सबसे छोटी इकाई है । जिसका आकार गांव से बड़ा होता है और इसके निवासी नगरीय जीवन व्यतीत करते हैं । 5,000 से 9,999 की जनसंख्या वाली नगरीय बस्ती को कस्बा कहते हैं ।

नगर (City): यह कस्बा से बड़ी बस्ती होती है । इसकी जनसंख्या 10,000 से 99,999 होती है । यहां कस्बों से अधिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं । यहाँ आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां होती हैं ।

महानगर (Metropolis): यह बड़े नगर होते हैं । इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है । जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इलाहाबाद आदि ।

मिलियन सिटी (Million City): इसे 10 लाखी नगर कहते हैं क्योंकि इस की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है ।

सन्नगर (Conurbation): जब नगर या महानगर का विकास इतना अधिक हो जाता है कि वह अपने प्रशासनिक सीमाओं से बाहर फैल कर अन्य कस्बों या ग्रामों को अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है तो इन उपनगरों या मुख्य नगर की एकत्रित बस्ती को सन्नगर कहते हैं । भारत में सन्नगर दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के निकट देखे जा सकते हैं ।

विराटनगर या वृहन्नगर (Megalopolis): यह सन्नगर की भांति विकसित होते हैं । जब एक महानगर या सन्नगर अधिक विकसित होकर आसपास के नगरों को भी अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है तो वह विराटनगर कहलाता है । इसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है ।

भारतीय नगरीय बस्तियों की विशेषताएं

अधिकांश लोग उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, प्रशासन आदि जैसे द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय में जुड़े होते हैं । शिक्षा, कला, प्रशासन और आमोद-प्रमोद के साधन उपलब्ध होते हैं । मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं । बाजारों में भीड़

रहती है । ऐसा भूमि के अभाव के कारण होता है । कानून और व्यवस्था के लिए थाना, कचहरी तथा अन्य सरकारी तंत्र उपस्थित होते हैं । परिवहन एवं संचार के साधनों की पूर्ण व्यवस्था होती है ।

नगरीकरण की समस्याएं

नगरीकरण के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार 7933 शहरों वाला भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है । इस प्रकार हर साल कस्बे नगर बन रहे हैं और नगर महानगर । इस विस्फोटक वृद्धि ने कई समस्याएं पैदा की हैं ।

स्थान की समस्या

बढ़ती जनसंख्या के कारण अत्यधिक भूमि की आवश्यकता होती है जो भौतिक तथा भौगोलिक दबाव के कारण आसानी से उपलब्ध नहीं होती । जब नगरों की वृद्धि होती है तो परिधि की ओर या ग्रामीण क्षेत्रों में कालोनिया बनने लगती हैं । इससे प्रमुख कृषि भूमि पर भारी दबाव पड़ता है तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवास आदि बनाने के लिए इस भूमि पर अतिक्रमण होता है ।

स्वास्थ्य समस्याएँ

तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण और शहरों की जनसंख्या में हो रही बढोतरी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रमुख चुनौतियों के रूप में देखा जाता रहा है। अनुमान है कि 1990 और 2025 के बीच विकासशील देशों में शहरी आबादी में तीन गुना वृद्धि हो चुकी होगी और यह कुल जनसंख्या के 61 प्रतिशत के बराबर हो जाएगी। इस बढ़ती हुई शहरी आबादी को देखते हुए पानी, पर्यावरण, हिंसा और चोट , गैर संचारी रोगों जैसी स्वास्थ्य संबंधी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, तम्बाकू के उपयोग, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक अकर्मण्यता और महामारियों के फैलने से जुड़ी आशंकाएँ और खतरे भी कोई कम चुनौतीपूर्ण नहीं हैं।

रोजगार की समस्या

जिस अनुपात में नगरों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही है। गाँवों से शहरों में आने वाले लोगों की अधिक संख्या के कारण उन्हें शहरों में कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है जिससे सामाजिक अव्यवस्था बढ़ती चली जाती है।

आवास की समस्या

विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है जिससे मकानों की कमी हो जाती है । एक अनुमान के अनुसार भारतीय नगरों में प्रतिवर्ष लगभग 1.7 मिलियन मकानों की कमी हो जाती है ।

बढ़ती असामनता

शहर की आबादी का लगभग एक तिहाई गरीबी रेखा से नीचे रहता है। योजना आयोग के अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या का पांचवा भाग झुग्गी-झोंपड़ी में रहता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार बंगलुरू में 10 प्रतिशत, कानपुर में 17 प्रतिशत, मुंबई में 38 प्रतिशत तथा कोलकाता में 42 प्रतिशत लोगों के सामने आवास की कठिन समस्या है।

अनियोजित नगरीकरण

यूएनडीपी के मुताबिक 70% भारतीय आबादी बाढ़ के खतरे और 60% भूकंप से प्रभावित है। घनत्व और अतिसंवेदनशीलता के कारण शहरी क्षेत्रों में जोखिम अधिक है। साल 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ को भुला नहीं जा

सकता | इस बाढ़ से दक्षिण भारत के कई बड़े शहर डूब गए थे | इसके कारण 300 लोग मारे गए थे, 18 लाख से अधिक आबादी का जीवन प्रभावित हुआ था और 20 हज़ार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था । केरल में आए बाढ़ ने पिछलें 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसमें 370 से अधिक लोगों की जाने गई| यह अनियोजित शहरीकरण का ही परिणाम है|

सामाजिक सुख सुविधाओं की कमी

नगरीय क्षेत्रों में लोगों के केंद्रीकरण के कारण सामाजिक सुख-सुविधाएं जैसे आवास, बिजली, पीने का पानी, परिवहन, सफाई का प्रबंध, गंदे पानी को हटाने का प्रबंध, शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, उद्यान, खेल के मैदान तथा मनोरंजन की सुविधाओं पर अधिक भार पड़ रहा है । वास्तव में नगरों में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन यहां आधारभूत संरचना तथा नागरिक सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं ।

मलिन बस्तियों में वृद्धि

यह निम्न स्तरीय अस्थाई अधिवास होते हैं, जहां बुनियादी सेवाओं का अभाव होता है । मलिन बस्तियों में एक या दो कमरों की झोपड़पट्टियाँ होती है जो अधिकांश सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित होती हैं । मध्य मुंबई में **धारावी** झोपड़ियां एशिया की सबसे बड़ी झोपड़ी है। यहां की सड़कें इतनी संकीर्ण हैं कि एक साइकिल भी पास नहीं हो सकती।

बढ़ते अपराध

शहरों में बढ़ते अपराध राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है| वर्ष 2015 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक दस लाख की आबादी से अधिक के 53 बड़े शहरों में अपराध बढ़े है| देश की राजधानी दिल्ली में 25 फीसदी अपराध दर्ज हुए| यह संख्या 1.73 लाख है| इसके बाद मुंबई (42,940), बेंगलुरु (35,576), कोलकाता (23,990) तथा हैदराबाद (16,965) का स्थान है| चेन्नई महानगरों में सबसे असुरक्षित है, जहां से 13,422 घटनाएं सामने आई है|वहीं सबसे असुरक्षित शहरों की लिस्ट में बिहार का पटना, राजस्थान का जोधपुर और केरल का कोल्लम भी शामिल हैं| हत्या के मामलों में दिल्ली (464), पटना (232) और बेंगलुरु (188) सबसे असुरक्षित शहरों में हैं|

प्रदूषण

विगत वर्षों में नगरों के झुरमुट पैदा हो गए हैं, जहां उद्योगों तथा वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है । फलतः पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आई है । यह गिरावट वायु, जल, ध्वनि तथा अपशिष्ट पदार्थों के प्रदूषण के कारण उत्पन्न हुई है । इससे नगर निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

परिवहन की समस्या

परिवहन मार्ग अवरुद्ध और भीड़-भाड़ भारतीय नगरों की प्रमुख समस्या है । भारत में ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ लोग ट्रैफिक की समस्या से परेशान न हो । देश के नगरों में सड़क परिवहन की दृष्टि से दिल्ली की स्थिति सबसे अच्छी है । यहां प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों की लंबाई का औसत 1284 किलोमीटर है । हालाँकि दिल्ली के अधिकांश सड़कों पर उनकी क्षमता से अधिक आवागमन होता है ।

जलापूर्ति की समस्या

मानव जीवन में जल का विशेष महत्व है । इसके बिना वह जीवित नहीं रह सकते । यही कारण है कि प्राचीन काल से ही नगरों की स्थापना जल स्रोतों के निकट की जाती रही है । आधुनिक नगरों में घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं हेतु बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है ।

उपर्युक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 29 अप्रैल 2015 को अटल मिशन (शहरी रूपांतरण एवं नवीनीकरण-अटल मिशन) शुरू किया गया है जिसका प्रमुख उद्देश्य शहरों को रहने के अधिक योग्य बनाना और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देना है ।

कुछ अन्य समस्याएँ

- शहरों की सड़कों पर गड्ढे, सीवर प्रणाली का अभाव एवं जल-जमाव से होने वाली परेशानियाँ, बिजली, पानी एवं संचार सुविधाओं का अस्त-व्यस्त व असमान रूप शहरी जीवन को इतना अधिक समस्यामूलक बना देता है कि कई शहरों में जाने की कल्पना मात्र से सिहरन होने लगती है।
- अपराध की दृष्टि से भी शहर तुलनात्मक रूप से अधिक असुरक्षित हैं...कंक्रीट के जंगल में रहने वाले लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते।
- भावनाशून्यता, संवादहीनता और व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति शहरी जनसंख्या के जीवन का हिस्सा बन गई है।
- नगरीय HEAT ISLAND प्रभाव
- बाल अपराध, भीख, ड्रग्स और नशाखोरी, भ्रष्टाचार आदि

इस प्रकार भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति बेहद विस्फोटक होती जा रही है जो अनेक समस्यायों की जननी है । समय रहते यदि हम इसके नियंत्रण के उपाय कर ले तो ठीक है वर्ना नगर आने वाले दिनों में रहने योग्य नहीं रह जायेंगे ।

- *सन्दर्भ: भारत का भूगोल: महेश बर्णवाल, एनसीईआरटी, इन्टरनेट*

****